ASSOCHAM IN THE NEWS

Punjab Kesari Page 17 21 July, 2019

सरकार को विमान सेवा कंपनी नहीं चलानी चाहिएः हरदीप पुरी

नई दिल्ली, (वार्ता): नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि निजी तौर पर उनकी राय यह है कि सरकार को विमान सेवा कंपनी नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास अरबों डॉलर पड़े हैं तो उसे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचों जैसे मकान, टॉयलेट आदि पर खर्च किया जाना चाहिए न कि एक ऐसे जोखिम भरे कारोबार में जिससे गरीबों का कोई भला नहीं होता है। श्री पुरी ने उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा नागर विमानन एवं कार्गो पर यहाँ आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह भी कहा कि यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है तथा विमान की सुरक्षा के बारे में यदि विमान बनाने वाली कंपनी को संदेह है तो उसे उस विमान की बिक्री ही नहीं करनी चाहिये। श्री पुरी नागर विमानन मंत्री होने के साथ ही 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूबी सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नये सिरे से गठित मंत्रियों के समूह के सदस्य भी हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि एयर इंडिया की अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है। पिछले दिनों उन्होंने एक विमान बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से साफ कह दिया कि यदि कंपनी को विमान की सुरक्षा के बारे में पूरा भरोसा नहीं है तो बेहतर होगा कि वह उस विमान को बाजार में उतारे ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने गत दिनों बारिश के दौरान कई विमानों के रनवे से फिसलने के संदर्भ में डीजीसीए को निर्देश दिया है कि हर ऐसी घटना की भी जाँच की जाये जिसमें दुर्घटना हुई नहीं, लेकिन होते-होते रह गयी। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में विमान एवं इंजन निर्माता कंपनियाँ मुनाफा कमा रही हैं, हवाई अड्डा संचालक मुनाफा कमा रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र भी मुनाफे में है जबकि एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है। यदि विमान सेवा कंपनियों की कुल लागत का 40 प्रतिशत विमान ईंधन पर खर्च हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है। श्री पुरी ने कहा कि निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज की सेवा बंद होने के बाद बाजार में सीटों की उपलब्धता में जो कमी आयी थी अब उसकी भरपाई हो चुकी है।

● यदि सरकार के पास अरबों डॉलर पड़े हैं तो उसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचों जैसे मकान, टॉयलेट आदि पर खर्च किया जाना चाहिए न कि एक ऐसे जोखिम भरे कारोबार में जिससे गरीबों का कोई भला नहीं होता

ASSOCHAM IN THE NEWS

NavodayaTimes Page 13 21 July, 2019

यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: पुरी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (एजेंसी): केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने विमान किराए में वृद्धि से जुड़ी धारणा को गलत बताया। उद्योग मंडल एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पर गौर करने को एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।

उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि नागर विमानन के कई क्षेत्रों में पहले ही 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का प्रावधान है लेकिन बजट में दो क्षेत्रों (रखरखाव एवं मुरम्मत व लीजिंग) में एफ.डी.आई. पर खास तौर पर बात की गई है। पुरी ने कहा कि वह आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय के 100 दिन के कार्यक्रम और 5 साल के दृष्टि पत्र पर काम कर रहे हैं। पुरी के मुताबिक उन्होंने नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) को सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विमान किरायों की हद तय करना व्यवस्था के साथ तोड़-मरोड़ करने के समान होगा।

यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता : पुरी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (एजेंसियां)। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है तथा विमान की सुरक्षा के बारे में यदि विमान बनाने वाली कंपनी को संदेह है तो उसे उस विमान की बिक्री ही नहीं करनी चाहिए।

पुरी ने उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा नागर विमानन एवं कार्गो पर यहां आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह भी कहा कि निजी तौर पर उनकी राय यह है कि सरकार को विमान सेवा कंपनी नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास अरबों डॉलर पड़े हैं तो उसे

सार्वजनिक बुनियादी ढांचों जैसे मकान, टॉयलेट आदि पर खर्च किया जाना चाहिए न कि एक ऐसे जोखिम भरे कारोबार में जिससे गरीबों का कोई भला नहीं होता है। पुरी नागर विमानन मंत्री होने के साथ ही 55 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नए सिरे से

सरकार को सार्वजनिक बुनियादी ढांचों जैसे मकान, टॉयलेट आदि पर खर्च किया जाना चाहिए न कि एक ऐसे जोखिम भरे कारोबार में जिससे गरीबों का कोई भला नहीं होता है : हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री

गठित मंत्रियों के समूह के सदस्य भी हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि एयर इंडिया की अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है।

पुरी ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने एक विमान बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से साफ कह दिया कि यदि कंपनी को विमान की सुरक्षा के बारे में पूरा भरोसा नहीं है तो बेहतर होगा कि वह उस विमान को बाजार में उतारे ही नहीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने गत दिनों बारिश के दौरान कई विमानों के रनवे से फिसलने के संदर्भ में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया है कि हर ऐसी घटना की भी जांच की जाए जिसमें दुर्घटना हुई नहीं, लेकिन होते-होते रह गई।

उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में विमान एवं इंजन निर्माता कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, हवाई अड्डा संचालक मुनाफा कमा रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र भी मुनाफे में है जबकि एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Virat Vaibhav Page 15 21 July, 2019

यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: नागरिक उड्डयन मंत्री

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विमान किराए में वृद्धि से जुड़ी धारणा को गलत बताया। उद्योग मंडल एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पर गौर करने को एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।

उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि नागर विमानन के कई क्षेत्रों में पहले ही 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान है लेकिन बजट में दो क्षेत्रों-रखरखाव एवं मरम्मत एवं लीजिंग-में एफडीआई पर खास तौर पर बात की गई है। पुरी ने कहा कि वह आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय के 100 दिन के कार्यक्रम और पांच साल के दृष्टि पत्र पर काम कर रहे हैं। पुरी के मुताबिक उन्होंने नागर विमानन महानिदेशालय को सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा, डीजीसीए को अपना काम मालूम है। मुझे नहीं मालूम कि डीजीसीए पहले क्या करता रहा है लेकिन सुरक्षा को लेकर मेरा निर्देश बिल्कुल साफ है कि किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा, उन्हें हर घटना का विश्लेषण करना होता है। हमें उम्मीद है कि हाल के सप्ताहों में जो घटनाएं हुई हैं, वह भविष्य में फिर से ना हो। विमान किरायों की हद तय करना व्यवस्था के साथ तोड़-मरोड़ करने के समान होगा। पुरी ने कहा, विमान किरायों के ऊपर चढ़ने की बात गलत है। एयरलाइन एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं, जहां वे अपनी वेबसाइट पर न्यूनतम से लेकर अधिकतम किराए का उल्लेख करते हैं।

यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता: पुरी

नई दिल्ली एजेंसी

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है तथा विमान की सुरक्षा के बारे में यदि विमान बनाने वाली कंपनी को संदेह है तो उसे उस विमान की बिक्री ही नहीं करनी चाहिए। पुरी ने उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा नागर विमानन एवं कार्गो पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह भी कहा कि निजी तौर पर उनकी राय यह है कि सरकार को विमान सेवा कंपनी नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास अरबों डॉलर पड़े हैं तो उसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचों जैसे मकान, टॉयलेट आदि पर खर्च किया जाना चाहिए न कि एक ऐसे जोखिम भरे कारोबार में जिससे गरीबों का कोई भला नहीं होता है। पुरी नागर विमानन मंत्री होने के साथ ही 55 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नए सिरे से गठित मंत्रियों के समूह के सदस्य भी हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि एयर इंडिया की अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है। पुरी ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने एक विमान बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से साफ कह दिया कि यदि कंपनी को विमान की सुरक्षा के बारे में पूरा भरोसा नहीं है तो बेहतर होगा कि वह उस विमान को बाजार में उतारे ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने गत दिनों बारिश के दौरान कई विमानों के रनवे से फिसलने के संदर्भ में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया है कि हर ऐसी घटना की भी जांच की जाए जिसमें दुर्घटना हुई नहीं, लेकिन होते-होते रह गई। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में विमान एवं इंजन निमार्ता कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, हवाई अड्डा संचालक मुनाफा कमा रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र भी मुनाफे में है जबकि एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि विमान सेवा कंपनियों की कुल लागत का 40 प्रतिशत विमान ईंधन पर खर्च हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है। पुरी ने कहा कि निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज की सेवा बंद होने के बाद बाजार में सीटों की उपलब्धता में जो कमी आयी थी अब उसकी भरपाई हो चुकी है। बीच में कुछ मार्गों पर हवाई किराये में वृद्धि जरूर हुई थी लेकिन अब किराया सामान्य हो गया है।

Loksatya Page 9 21 July, 2019

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित

यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

❑ पुरी ने कहा कि यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है परंतु विमान की सुरक्षा के बारे में यदि विमान बनाने वाली कंपनी को संदेह है, तो उसे उस विमान की बिक्री ही नहीं करनी चाहिये।

नई दिल्ली,एजेंसी।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है तथा विमान की सुरक्षा के बारे में यदि विमान बनाने वाली कंपनी को संदेह है तो उसे उस विमान की बिक्री ही नहीं करनी चाहिये।

श्री पुरी ने उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा नागर विमानन एवं कार्गो पर यहाँ आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह भी कहा कि निजी तौर पर उनकी राय यह है कि सरकार को विमान सेवा कंपनी नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास अरबों डॉलर पड़े हैं तो उसे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचों जैसे मकान, टॉयलेट आदि पर खर्च किया जाना चाहिए न कि एक ऐसे जोखिम भरे कारोबार में जिससे गरीबों का कोई भला नहीं होता है।

श्री पुरी नागर विमानन मंत्री होने के साथ ही 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूबी सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नये सिरे से गठित मंत्रियों के समूह के सदस्य भी हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि एयर इंडिया की अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है।

श्री पुरी ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने एक विमान बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से साफ कह दिया कि यदि कंपनी को विमान की सुरक्षा के बारे में पूरा भरोसा नहीं है तो बेहतर होगा कि वह उस विमान को बाजार में उतारे ही नहीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने गत दिनों बारिश के दौरान कई विमानों के रनवे से फिसलने के संदर्भ में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया है कि हर ऐसी घटना की भी जाँच की जाये जिसमें दुर्घटना हुई नहीं, लेकिन होते-होते रह गयी।

उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में विमान एवं इंजन निर्माता कंपनियाँ मुनाफा कमा रही हैं, हवाई अड्डा संचालक मुनाफा कमा रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र भी मुनाफे में है जबकि एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। यदि विमान सेवा कंपनियों की कुल लागत का 40 प्रतिशत विमान ईंधन पर खर्च हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Pioneer (Hindi) Page 11 21 July, 2019

यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: नागरिक उड्डयन मंत्री

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विमान किराए में वृद्धि से जुड़ी धारणा को गलत बताया।

उद्योग मंडल एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पर गौर करने को एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि नागर विमानन के कई क्षेत्रों में पहले ही 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान है लेकिन बजट में दो क्षेत्रों--रखरखाव एवं मरम्मत एवं लीजिंग-में एफडीआई पर खास तौर पर बात की गई है। पुरी ने कहा कि वह आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय के 100 दिन के कार्यक्रम और पांच साल के दृष्टि पत्र पर काम कर रहे हैं। पुरी के मुताबिक उन्होंने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा, डीजीसीए को अपना काम मालूम है। मुझे नहीं मालूम कि डीजीसीए पहले क्या करता रहा है लेकिन सुरक्षा को लेकर मेरा निर्देश बिल्कुल साफ है कि किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा, उन्हें हर घटना का विश्लेषण करना होता है। हमें उम्मीद है कि हाल के सप्ताहों में जो घटनाएं हुई हैं, वह भविष्य में फिर से ना हो। उन्होंने कहा कि विमान किरायों की हद तय करना व्यवस्था के साथ तोड़-मरोड़ करने के समान होगा। पुरी ने कहा, विमान किरायों के ऊपर चढ़ने की बात गलत है। एयरलाइन एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं, जहां वे अपनी वेबसाइट पर न्यूनतम से लेकर अधिकतम किराए का उल्लेख करते हैं।